

भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1469

दिनांक 10.02.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रथम सहायता चैनल

1469. श्री कोडिकुन्नील सुरेश

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या सरकार ने इन रिपोर्टों को संज्ञान में लिया है कि लगभग 80,000 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवर, जो एच-1 बी और एल-1 जैसे गैर-आप्रवासी कार्य वीजा पर हैं, को रोजगार से निकाला जा रहा है और वे संयुक्त राज्य अमेरिका में गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार राजनयिक चैनलों से इन व्यक्तियों को किसी भी तरीके से संभावित तत्काल मदद और सहायता प्रदान करेगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार विदेशों में रह रहे भारतीयों की सहायता के लिए प्रथम सहायता चैनल के रूप में विभिन्न दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में व्यावसायिक और रोजगार सहायता प्रकोष्ठ स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) से (ङ.) सरकार को हाल के महीनों में अमेरिकी कंपनियों द्वारा पेशेवरों की छंटनी के मुद्दे की जानकारी है। इन कार्मिकों में से कुछ प्रतिशत एच-1 बी और एल 1 वीजा पर गए भारतीय नागरिकों के होने की संभावना है।

भारत सरकार ने आईटी पेशेवरों सहित उच्च कुशल कार्मिकों की आवाजाही से संबंधित मुद्दों को लगातार अमेरिकी सरकार के साथ उठाया है। सरकार इन मुद्दों पर उद्योग संगठनों और व्यापार मंडलों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ भी काम कर रही है।
